**Sixteenth Loksabha**

an>

Title: Further discussion on the motion for consideration of the Requistioning and Acquistion of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017, moved by Shri Hardeep Puri on 19 December, 2017 (Discussion Concluded and Bill Passed).

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, I request that further consideration of the motion moved by Shri Hardeep Singh Puri yesterday, on the 19th December, 2017, may be taken up now. The motion is as follows:

> "That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, be taken into consideration."

HON. DEPUTY-SPEAKER: All right. Shri Ramesh Bidhuri may continue now.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: There is no 'Zero Hour' now.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Already hon. Speaker has disallowed it. So, I cannot allow you now.

… (*Interruptions*)

**श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली):** सर, कल मैं रिक्विजिशनिंग एंड एक्वीजिशन ऑफ इममूवेबल प्रॉपर्टी (अमेंडमेंट) बिल, 2017 के बारे में बोल रहा था। माननीय शहरी विकास मंत्री आदरणीय श्री पुरी जी इस बिल को लेकर आए हैं। ...(व्यवधान)

महोदय, यहां जो लोग शोर मचाने के लिए खड़े हुए हैं, उनके संज्ञान में लाने के लिए, मैं इस बिल के बारे में बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) सर यह बिल देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, देश के डिफेंस के लिए जो जमीन हम लोग रिक्विजिशन के रूप में सेक्शन-3 के द्वारा एक्वायर करते हैं और जब सेक्शन-7 के द्वारा उसकी

पेमेंट करने की बात चलती है, अगर इस बीच वह मैटर जूडिशियरी में चला जाता है तो वहां उन जमीनों की व्यवस्था नहीं हो पाती है और देश की सुरक्षा में बाधा आती है।..(व्यवधान) इससे सरकार के करोड़ों-अरबों रुपये वहां खर्च होते हैं।...(व्यवधान) ऐसे कुछ केसेज भी हमारे सामने हैं, जहां आठ से दस हजार करोड़ रुपये की डिमाण्ड लोग रखते हैं। कानून के द्वारा अगर डिफेंस के लिए या नेशनल सिक्योरिटी के लिए लैण्ड एक्वायर की जाती है तो कोई आधा एकड़, एक एकड़ या दो एकड़ जमीन एक्वायर नहीं की जाती है। ...(व्यवधान) मैंने यह बात कल भी कही थी और आज हमारे जो साथी वहां खड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इस तरह से सैकड़ों-हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की जाती है। ...(व्यवधान) वहां पर कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं...(व्यवधान) तमिलनाडु में शिवपुरी का केस आपके सामने है, पैरामिलिटरी फोर्स के नाम से जो जमीन है, उसके आस-पास किस फाइनेंस मिनिस्टर या किस गृह मंत्री की जमीन है, वह बात किसी से छिपी हुई नहीं है।...(व्यवधान) इन्हीं की पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर थे। वे लोग क्या करते हैं? जब हम रिक्विजिशन के लिए सेक्शन-3 का नोटिस देते हैं।

नोटिस के बाद सैक्शन 7 का नोटिफिकेशन उस जमीन को एक्वॉयर करने के लिए देते हैं तो नोटिसेज का बहाना बनाकर एज एन एप्लीकेंट वे लोग कोर्ट में चले जाते हैं। जो जमीन हम लम्बे समय तक एक्वायर करते हैं, वह कभी न कभी कृषि भूमि के रूप में ले रखी होती है और उसमें कंडीशन होती है कि जमीन को जब सरकार वापस लौटायेगी तो इसी स्थिति में लौटाएगी। उसमें यह कंडीशन होती है लेकिन बाद में सरकार सोचती है कि जमीन को हम खरीद लें। इस बीच वे नोटिस का बहाना बनाकर कोर्ट में चले जाते हैं। पिछले 70 सालों में कांग्रेस के लोग देश में किस प्रकार के नैक्सेज पैदा करते रहे हैं, यह बात किसी से छिपी नहीं है। टू जी स्पैक्ट्रम का मामला आपके सामने है। कोल घोटाले का मामला आपके सामने है। आदर्श सोसायटी का केस आपके सामने है। इस प्रकार के जो स्कैम्स होते थे, इन स्कैम्स से बचने के लिए उस जमीन को सरकार टेक-ओवर कर ले, टेक-ओवर करने के बाद सरकार उस जमीन के पैसे देगी, लेकिन जिस समय का नोटिस होगा। लेकिन 15 साल तक जानबूझकर ज्यूडिशियरी में केसों को लटकाकर, लम्बित करके कि अगर उस जमीन का पैसा मिल जाएगा तो वे लोग ब्लैक-मनी को कहां रखेंगे। वे समझते हैं कि कोर्ट हमारे फेवर में ऑर्डर कर देगा। सरकार से तब के रेट के पैसे, 15 साल-12 साल रेट के पैसे वे मांगते हैं। वे सोचते हैं कि वे पैसे हमें मिल जाएंगे। इस प्रकार से सरकार को अरबों रुपये का चूना लगता है। जो पैसा देश के विकास में लगना चाहिए, उससे बचने के लिए यह बिल लाया गया है। जो नोटिफिकेशन के समय पर उसकी कीमत थी, अभी भी सरकार उनको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पैटर्न पर जो फिक्सड डिपॉजिट एमाउंट होता है, अगर मैं आज कोई फिक्सड डिपॉजिट एमाउंट जमा कराऊं और जो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इस बिल के माध्यम से वह पैसा उसको मिलेगा वर्ना मेरे बन्धु और मेरे अपोजिशन के मित्र यह भी शोर मचाएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकार तानाशाह के रूप में इस बिल को लेकर आ रही है।

मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देता हूं। वऐान 2005 में एजुकेशन कम्पलसरी एक्ट आया था। आज भी देश में कानून है कि एजुकेशन कम्पलसरी होनी चाहिए। दिल्ली के वाइस-चांसलर ने चार चिट्ठियां दिल्ली के सी.एम. को लिखीं कि दक्षिणी दिल्ली में लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं है। 70 साल देश को आज़ाद हुए हो गये हैं। ये लोग पिछले 70 सालों से देश पर राज करते रहे हैं। पिछले दस सालों तक इनकी सरकार थी, लेकिन दिल्ली में लड़कियों के लिए एक नया कॉलेज नहीं खोला गया। हमारे प्रधान मंत्री जी ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा दिया है और इससे अगर लड़कियों को सम्मान मिलेगा, उनको एजुकेशन मिलेगी तो कॉलेज खुलना चाहिए। वाइस-चांसलर दो-दो, तीन-तीन चिट्ठियां दिल्ली के सी.एम. को लिख चुके हैं। मैं मुख्य मंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर से मिल चुका हूं, लेकिन दिल्ली के मुख्य मंत्री आज तक उस ग्राम पंचायत की जमीन पर कॉलेज नहीं बनाने दे रहे हैं। वह जमीन

ग्राम पंचायत की है, गांव वालों की जमीन है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि उस जमीन पर कॉलेज बनाने नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से यह कानून ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए है। जो नैरो-माइंडेड लोग हैं, जो निजी स्वार्थों के लिए देश के साथ, देश की सम्पदा के साथ, देश की जनरेशन के साथ सौदा करते हैं, उन निजी स्वार्थी तत्वों से देश को बचाने के लिए इस बिल को लाया गया है।

मेरे पास इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं। हमने एक गांव गोद लिया। उसको आदर्श गांव बनाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि एक सैम्पल के रूप में गावों का विकास होगा। यदि उन गांवों का विकास होगा तो निश्चित रूप से उनको देखकर अपने गांवों में और भी स्वच्छ वातावरण में जीने के लिए लोगों को एक मोटीवेशन मिलेगा। लेकिन वहां पर कोई लड़कियों का स्कूल खोलना है, वहां पर बच्चों की शादी के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाना है, वहां पर कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस की ब्रान्च खोलनी है तो सिसोदिया साहब, जो दिल्ली के उप मुख्य मंत्री हैं, डवलपमेंट कमिश्नर जो वहां की थीं, जब मैंने उनको यह कहा कि मैं इनके घर पर जाकर धरने पर बैठ जाऊंगा यदि ये जमीन नहीं देंगी तो वह मुझसे कहती हैं कि बिधूड़ी साहब, आप इसमें राजनीति मत करिए।

सर, ये इससे रिलेटेड चीजें हैं। यह कानून क्यों लाया गया? बाद में बहुत लोग शोर मचाएंगे कि यह कानून तो लोगों के अधिकारों को छीनने के लिए लाया जा रहा है। यह कानून देश की सम्पदा को बचाने के लिए लाया जा रहा है और देश की जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। इसीलिए मैं इस बिल पर बोल रहा हूं। इसीलिए मैं एग्जामपल दे रहा हूं। वह डी.सी. मुझसे कहती हैं कि मैं डिप्टी सी.एम. साहब से बात कर लूंगी। डिप्टी सी.एम. साहब उनसे कहते हैं कि बिधूड़ी से कहो कि वह डी.डी.ए. से जमीन ले लें। वह डवलपमेंट कमिश्नर कहती हैं कि बिधूड़ी साहब, ये इतनी छोटी सोच के लोग हैं, मैं तो इनके नीचे नौकरी नहीं करूंगी और वह डी.सी. वहां से नौकरी छोड़कर सेन्ट्रल गवर्नमेंट में आ गयीं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि खड़गे जी की टीम के ये जो लोग 70 सालों से देश में राज कर रहे हैं, ऐसे लोगों से इस देश को बचाने के लिए इस बिल को लाया गया है। इस लॉ के माध्यम से, इस बिल के माध्यम से अब डिजनीलैंड या जीजा-साले को जमीन अलॉट करने का प्रोविजन नहीं है।

यह जमीन केवल देश को डिफेंस के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए, ऑब्लाइज करने के लिए मिले, न कि यह कहीं ...* ो जमीन एलॉट की जायेगी, उस काम के लिए यह बिल नहीं है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश में जो प्रधान मंत्री जी की सोच रही है कि देश की सीमायें...(व्यवधान)

**माननीय उपाध्यक्ष :** श्री कल्याण बनर्जी।

…(व्यवधान)

**श्री रमेश बिधूड़ी :** सर, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।...(व्यवधान) हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी, हमारे मंत्री जी की यह योजना होगी कि इस बिल के माध्यम से हम देश के नौजवान और देश की सीमा पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) ऐसे कड़े फैसले लेंगे, इस बात के लिए इस बिल को लायेंगे। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। ... (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Hon. Deputy Speaker, Sir, the Bill which has been brought before this House for consideration is the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017. … (*Interruptions*) Through this Bill, an amendment is sought to be brought under Clause 2, Sub-Clause 1(a). … (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Deputy Speaker, Sir, during 'Zero Hour', one Member was allowed. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, there is no 'Zero Hour'. We are discussing the Bill moved by the hon. Minister.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, I am on a point of order. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I have heard. There is no 'Zero Hour' now.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, by this Clause, an opportunity of hearing is being given which was not there earlier. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: You are saying about expunction. What should I expunge? There is nothing.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : During 'Zero Hour', a Member was allowed. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: There is no 'Zero Hour' now.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, the House was adjourned around 12 o'clock. After that, we are meeting just now. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now the business before the House is different. We have taken up the Bill for consideration.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: There is no 'Zero Hour' now. When 'Zero Hour' comes, you can raise it at that time.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, Clause 2, Sub-clause 1(a) which is sought to be brought is really filling up the gaps. … (*Interruptions*) A reasonable opportunity of hearing is being given under this provision. … (*Interruptions*) I have no objection. … (*Interruptions*) This is beneficial to the person who is going to be affected. … (*Interruptions*) We have to go back to the history and see why this Act was enacted in the first place. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Kharge, you can raise it tomorrow.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: What is your point of order?

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKE: A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment. This is what the rule says.

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please listen to me. Any point of order should relate to the subject which is before the House now. Only that will go on record. All other things will not go on record.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, kindly give me a minute. … (*Interruptions*) Sir, we are not taking any objection to your decision. That is a different thing. The Member who spoke against Manmohan Singhji… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, nothing will go on record.

*...(Interruptions)...*[*]

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record. Only Mr. Kalyan Banerjee's speech will go on record.

… (*Interruptions*) ...[*]

SHRI KALYAN BANERJEE : Deputy Speaker, Sir, kindly, bring this House in order.… (*Interruptions*) I cannot speak. How can I speak in this way? … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record.

… (*Interruptions*) ...*

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, let the House be in order. If this is the way, I cannot speak. … (*Interruptions*) I have been interrupted fourth time.… (*Interruptions*) Let the House be in order. … (*Interruptions*) Otherwise, take up this issue some other day. … (*Interruptions*) No one can speak, Sir, in this way.… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Sir, only Congress Party wants to disturb the proceedings. … (*Interruptions*) Actually, there is no issue or no point of order. The entire House wants to conduct business of the House. … (*Interruptions*) They are creating obstructions. Therefore, I request my dear friend and colleague of Trinamool Congress Mr. Kalyan Banerjee to continue his speech. … (*Interruptions*) Already Ramesh Bidhuri ji has spoken. … (*Interruptions*) I also request him to continue his speech. … (*Interruptions*) Sir, they cannot hold 80 per cent of the House to ransom. … (*Interruptions*) Therefore, my request to you, Sir, is to continue the proceedings of the House. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Kalyan Banerjee, please continue your speech.

… (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, what I was telling is if we go back into the history of the Act itself, earlier the Defence of India Act was there.… (*Interruptions*) After Independence, when the Legislature felt that the Defence of India Act was not required and the rules were framed thereafter, the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 was brought.… (*Interruptions*) The initial intention of this legislation, at that point of time, was that for the time being a premise can be requisitioned.… (*Interruptions*) Any land can be requisitioned for the use of the Central Government. … (*Interruptions*) There is no difficulty. Now, as you know, requisition cannot be continued until doomsday. … (*Interruptions*) Therefore, one has to take a decision whether it has to be released from the requisition or acquisition has to be taken. … (*Interruptions*) I just tell you, there are a number of cases where the acquisition proceeding was taken but it was not ended. … (*Interruptions*) No compensation has been given. … (*Interruptions*) Ultimately, because of the failure of the officials of the Central Government, who are concerned with this Department, so many acquisitions and requisitions have declared illegal and void. … (*Interruptions*) Therefore, the time has been ripening to take a decision whether you want to release it from the requisition or you want to acquire the property. …

(*Interruptions*) If you wish to acquire the property, do it immediately. Please do not keep it pending for long. … (*Interruptions*) This is not the ambit. Immediately, you do it. Actually, that is not happening. … (*Interruptions*) As a result thereof, ultimately, who is suffering? Lot of money is going out from the public exchequer. This is one of the reasons. … (*Interruptions*)

I can cite you a number of cases. At least in West Bengal, in Jalpaiguri and Darjeeling districts where military buildings have been made, Army structures have been made, still that requisition has not been completed. Even if it has been done, some procedural mistake is there; one is going to suffer. That is a different thing. … (*Interruptions*)

I would just like to put a very relevant question for your consideration. Parliamentary Affairs Minister is here; Law Minister is also here. To all, I have a request; you have to consider one aspect of the matter. In future, you have to come out with that. The compensation which has been assigned under the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, has been provided under Section 8 of the Act. In substance, nothing has been given as to what would be the amount of compensation. It is either by an agreement or by arbitration. Therefore, what are the principles? That has not been laid down. Now, with the passage of time, when acquisition was a strong question in our country, we have brought the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. We have brought it and it is under consideration. We are implementing it. We have repealed the old Land Acquisition Act itself where the compensation amount was very little. Under Section 26 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, you have given the principles of determination of compensation. The objective of the Government is that every land loser must get more compensation. That is the objective of the Act. That is also the objective of the Central Government. … (*Interruptions*)

My point is this. This is an old Act. Now you try to bring a *pari materia* provision akin to Section 26 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act in this Act itself, the Act in question itself in future so that compensation amount can be decided. There must be a formula of paying compensation. It cannot be by an agreement or an arbitrator cannot decide the question exactly without any basis, any guidelines or anything. I am really happy to see that an opportunity of hearing has been brought in here which is really commensurate with the principles of natural justice. It is a good thing but, in future, you have to think about that whether a *pari materia* provision akin to Section 26 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act can be brought under this Act itself. One must know what should be his compensation, the market value etc. It can be taken into consideration. Kindly take note of two things. This is one thing. … (*Interruptions*)

Secondly, it is my appeal to the hon. Minister; kindly give instruction to your Department. Take all cases of requisition and acquisition. Where requisition is continuing for 30 years, 40 years, it is not

required. It can be acquired. You acquire it; otherwise you just release it. There is no use of paying money. Some properties are there which are under requisition and the Central Government is also not using the properties. On the contrary, the Central Government is paying money. That is also a loss to the public exchequer. Kindly take into consideration that in future. That is my request. With this, I conclude. … (*Interruptions*)

**श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) :** उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 2017 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, देश आजाद होने के बाद से...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Under Rule 380, because in 'Zero Hour', ……. (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, it is not 'Zero Hour'. You talk about this Bill which is going on. …

(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : One hon. Member used defamatory words against the ex-Prime Minister who is not a Member of this House. Against him, those defamatory words were used. I request you to expunge all those words. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will go through that. …

(*Interruptions*).

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He should apologize for that. … (*Interruptions*) This is not fair. This is the point of order. We met even the Speaker also. She said that she will expunge that immediately. So far the matter is not expunged.

HON. DEPUTY SPEAKER: No, I will go through that. …

(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, it has been telecasted. If it goes in print media, the Government should apologize for that. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The Government will not come into this. You have already explained to the Speaker. …

(*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, hon. Speaker has assured us. … (*Interruptions*) It is in the record. It went on to the media also. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: We will go through that.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : So, Sir, we must be allowed to discuss this issue thoroughly so that the entire nation should know who is the traitor, who is back-stabbing and who is disturbing?

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever was said regarding this by the hon. Member in the morning, that will be gone through. …

(*Interruptions*)

**श्री गोपाल शेट्टी :** उपाध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस के मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा कर रहा है। जिनकी भूमि चली गयी है, उनको न्याय मिले, उनको पैसा मिले।...(व्यवधान) मोदी जी की सरकार देश में आयी है। जिनकी जमीनें डिफेंस में वऐाऩ 1952 के बाद जितने भी युद्ध हुए ऐसी जितनी जमीनों का रिक्वीजिश्न किया गया था, उसका न्याय अभी तक डिफेंस के लोगों ने नहीं किया है।...(व्यवधान) देश के इतिहास में पहली बार देश के लोगों ने मोदी जी की सरकार को चुनकर इस सदन में भेजा है और मोदी जी के द्वारा सत्ता सम्भालने के बाद से बहुत सारे परिवर्तन इस देश में देखने को मिल रहे हैं।...(व्यवधान) उसी के परिणामस्वरूप जिनकी भूमि का डिफेंस के लोगों ने रिक्वीजिशन किया था।...(व्यवधान)

महोदय, डिफेंस एस्टबिलिश्मेंट एक्ट यह कहता है कि जो जमीन एक बार रिक्वीजिश्न हो गयी, युद्ध समाप्त होने के बाद सम्मानजनक तरीके से उनका धन्यवाद अदा करके, जितनी जमीन का आपने उपयोग किया है,... (व्यवधान) उसका जो भी मुआवजा होता है, उसको धन्यवाद सहित दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान) यह व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से से चल रही है और हमारे ब्यूरोक्रेट्स उसी मानसिकता में आज भी काम कर रहे हैं।... (व्यवधान) 70 साल पहले जिन लोगों की जमीन ली गयी थी, उनको आज भी पैसा नहीं मिला है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever was said by the hon. Member, that was expunged. …

(*Interruptions*)

**श्री गोपाल शेट्टी :** मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा, मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छा बिल सदन में पारित करने के लिए वह लाए हैं और इस पर मुझे भी अपना मत व्यक्त करने का अवसर मिला है।...(व्यवधान)

महोदय, सेक्शन 3 कहता है कि युद्ध के समय में जब कभी भी आपको जमीन की आवश्यकता होती है तो आप रिक्विजिश्न कर सकते हैं।...(व्यवधान) सेक्शन 7 यह कहता है कि आपको अगर जमीन हमेशा के लिए चाहिए तो एक्विजिश्न करना होता है।...(व्यवधान) एक्विजिश्न एक्ट के मुताबिक जमीन का भाव उस समय जो भी होगा, वह जमीन का पैसा उसको देकर आप अपने नाम जमीन कर सकते हैं।...(व्यवधान) लेकिन हमारे डिफेंस

एस्टबिलिश्मेंट के लोग, जितना हमारे दुश्मन देश के लोगों को परेशान नहीं करते हैं, उतना हमारे देश के लोगों को परेशान करने का काम डिपार्टमेंट के माध्यम से हो रहा है।...(व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिफेंस एस्टबिलिश्मेंट के लोगों को जितनी जमीन चाहिए, उतनी ले लीजिए। जमीन एक्वायर करने के लिए सरकार की तिजोरी में पैसा होता है। यदि डिफेंस एस्टबिलिश्मेंट को और जमीन चाहिए तो जमीन खरीदने के लिए देश के लोग आपको पैसा देंगे। ...(व्यवधान) लेकिन अनावश्यक ढंग से किसी की भी जमीन एक्वीजीशन, रिक्वीजीशन करके एक्वीजीशन एक्ट के मुताबिक सारी फॉर्मैलिटीज़ पूरी किए बगैर आप किसी की भी जमीन ले लेते हो।

HON. DEPUTY SPEAKER: Whatever speech Shri Gopal Shetty is making will go on record. Whatever he is speaking will go on record.

**श्री गोपाल शेट्टी :** आपको मैं एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि देश के लोग किस प्रकार से परेशान हैं, जिनकी जमीनें गईं, वह तो गईं। रिक्वीजीशन के बाद आपने आज तक उसका न्याय नहीं किया जिसका नतीजा यह हुआ कि जो पैसे वाले लोग हैं, उन सब पैसे वाले लोगों ने एग्रीमेंट करा कर अपने नाम पर जमीन ले ली। आज जो भी एक्ट का लाभ मिलेगा, जिन्होंने जमीन अपने नाम पर ले ली उनको मिलेगा, लेकिन जिनकी मूल जमीन है, उनको कौड़ी मोल भी पैसा नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप लोगों को जानना चाहिए। अधिकारियों को तनख्वाह मिलती है, हम सांसदों को मानदण्ड मिलता है। हम दोनों का काम, लोकशाही में जो तीसरा व्यक्ति है, उसका काम सेवा करने का है। अंग्रेजी में जिसे सर्विस कहते हैं। अंग्रेजों ने जब बनाया तो यह सर्विस था। आप और हम, दोनों मिलकर लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं। ...(व्यवधान) लेकिन इन दिनों सर्विस कम और परेशान ज्यादा करने का काम ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से हो रहा है। इसलिए मैं आर.के. सिन्हा जी को धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया। मुम्बई जैसे शहर में जब डेवलपमेंट का काम चलता है...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I listened to whatever he said.

*...(Interruptions)*

**श्री गोपाल शेट्टी :** कांग्रेस के जमाने में सेंट्रल, ऑर्डीनेंस डिपो की जमीन, सभी बोगस इल्लीगल सर्कुलर निकालकर आपने सारे काम बंद कर दिए। आज भी दूसरे चरण में जब मैंने यहां प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I have already listened to what you said.

*...(Interruptions)*

**श्री गोपाल शेट्टी :** किस्मत से मेरा नम्बर भी लग गया। कल उसके ऊपर भी चर्चा होगी इसलिए मैं उस विऐाय पर जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह जो बिल आया है, इस बिल का समर्थन करते हुए, जिन लोगों की भी जमीन रिक्वीजीशन हुई है, उनको न्याय देने का काम मोदी जी की सरकार कर रही है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: He is on his legs.

**श्री गोपाल शेट्टी :** हमारे सारे मंत्री भी कर रहे हैं। इसलिए मैं उनको भी देश के तमाम लोगों की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। जो सामान्य लोगों की जमीन आपने रिक्वीजीशन की, आपने उनको 50 साल पैसे नहीं दिए। आज सरकार जो नियम लायी है कि उन दिनों में जो रेट था उसके साथ स्टेट बैंक का इंटरेस्ट का जो प्रोसीजर है तो

इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे देंगे। ...(व्यवधान) वैसे देखा जाए तो जमीन का मल्टीप्लीकेशन होते हुए आज के समय में उसकी बहुत कीमत है, लेकिन डिफेंस इस्टैब्लिशमेंट के लिए जमीन चाहिए। इसलिए मैं उन सारे मुद्दों पर जाना नहीं चाहूंगा। क्योंकि मैं सरकार के पक्ष में हूं, मैं चाहता हूं कि हमारा डिफेंस इस्टैब्लिशमेंट सक्षम हो। ...(व्यवधान) हमारे पड़ोसी मुल्क हमें परेशान करते हैं तो उनके साथ लड़ाई करने के लिए हमारे सिपाही और सेना का मनोबल बढ़े। इसलिए पूरा देश सेना के साथ है। ...(व्यवधान) लेकिन कुछ अधिकारी जो ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि हम देश के लोगों को न्याय देने के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं इस बिल के माध्यम से मानता हूं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा।

**14.33 hours** (Hon. Speaker *in the Chair*)

हमारे देश में बहुत से लोग भूमिहीन हो गए, बहुत सारे लोग मर गए। आप इतिहास निकालकर देख लीजिए। इस बिल के पास होने के बाद जब आप पैसे देंगे तो मूल मालिक कितने हैं और मूल मालिकों से पूंजीपतियों ने जो जमीन खरीदी थी, वे कितने हैं, आपको पता चलेगा कि मूल मालिक चले गए, गुजर गए, मर गए। उनकी संतान में जो बच्चे थे, उनकी जमीन होते हुए भी उन्हें पैसा नहीं मिला, वे कामकाज नहीं कर पाए। परिस्थिति इस प्रकार की भी देश में निर्मित हुई है कि बहुत सारे लोगों की जमीन होते हुए भी उनकी जमीन भी गई और पैसा भी नहीं मिला। इस प्रकार की भी स्थिति है। लेकिन देर से क्यों न हो, मैं सरकार को फिर एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छे बिल के माध्यम से लोगों को आज यहां न्याय देने का काम हो रहा है। ...(व्यवधान) इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से चाहूंगा कि आने वाले दिनों में जो भी अधिकारी इस प्रकार से मनमाने काम करके लोगों को परेशान करने का काम करते हैं, उनके ऊपर भी कोई न कोई अकाउन्टेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। यह बिल पास करने के बाद मैं इस सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि 50-60 साल से जिनके ऊपर अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, जिनकी जमीनें चली गईं, जो कुछ नहीं कर पाए ऐसे कितने लोग प्रभावित थे, उसका भी रिकॉर्ड इस सदन में आना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो अधिकारी इस प्रकार का काम करते हैं, उनको भी कोई न कोई सबक मिलेगा। हो सकता है बहुत सारे अधिकारी रिटायर होकर चले गए होंगे। आज के समय में जो अधिकारी हैं, उनका कोई दोऐा नहीं होगा। लेकिन आज के समय में भी यही सब चल रहा है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो डिफेंस इस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं उन्हें सड़क पर लड़ने का काम करना चाहिए, देश को सुरक्षित करने का काम करना चाहिए। बाकी सारे मामलों का काम पार्लियामेंट के माध्यम से जो सिस्टम काम कर रहा है। उस सिस्टम के लोगों को काम करना चाहिए। डिफैंस इस्टाब्लिशमैंट के लोगों को सिर्फ लड़ाई तथा दुश्मनों के लिए जो भी व्यवस्था करनी होती है, वह काम करने देना चाहिए। मैं अपनी आवाज देश भर के लोगों के माध्यम से इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

महोदया, मैं कह रहा था कि जब सीओडी का मामला निकला, तब मैं आपको मिला तो आप भी प्रभावित हो गईं, आपने हमें यहां चर्चा करने का मौका भी दिया। पर्रीकर साहब जैसे अच्छे मिनिस्टर ने बहुत मेहनत करके सर्कुलर निकाला, लेकिन उसमें सिर्फ नेवल का एड करना बाकी रहा, इसलिए फिर एक साल से लोग परेशान हैं। अधिकारियों को देश के मानस को समझना चाहिए, उन्हें सरकार के मानस को समझना चाहिए तथा पार्लियामैंट का जो मन और भाव है, उसे समझना चाहिए। टैक्निकल एरर को लेकर, छोटी-छोटी बातों को लेकर हमारे देश के

विकास को रोकने का यदि कोई काम करता है तो वह कितना उचित है, यह भी समझने की आवश्यकता है। एक जगह देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि 2022 तक सबको घर मिलना चाहिए, लोगों का अपना पक्का घर होना चाहिए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, वह उसमें कोई न कोई अड़ंगा पैदा कर डैवलपमैन्ट के काम को रोकने का काम करती है। इसके बारे में इस सदन को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। हम डिफैंस इस्टाब्लिशमैंट का बहुत सम्मान करते हैं। हमारी सेना दुनिया की नम्बर वन सेना है। अपनी जान को गंवाकर, अपने परिवार की चिंता न करते हुए वे इस देश के लोगों की चिंता करते हैं। लेकिन ऐसे समय पर जो एक दूसरा वर्ग है, वह बिल्कुल अपने ढंग से काम करते हुए परेशान करने का काम करता है। मैं चाहूंगा कि इस बिल के पास होते ही जितने भी लोगों को पैसा मिलने में देरी हुई है, एक टाइम बाउंड पीरियड तय करके जल्दी से जल्दी उन्हें पैसा मिले, उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। हम इस प्रकार अमैंडमैंट बिल लाकर सदन में चर्चा करके पास करते हैं तो लोगों को उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा बिल पास होने के बाद भी बहुत से लाभ नहीं मिल पाते हैं। मेरा 25-26 साल का अनुभव है, मैं तीन बार नगरसेवक, दो बार विधायक और छठी बार यहां आया हूं। होता क्या है कि बहुत सारे बिल पास होने के बाद भी उनका लाभ लोगों को नहीं मिलता है, यह भी हमने देखा है। इसलिए मैं संसद के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम जो भी बिल पास करते हैं, तीन या छः महीने में उनकी एक रिपोर्ट सदन के पास आनी चाहिए कि इन बिलों के पास होने के बाद इनका लाभ कितने लोगों को हुआ और कैसे हुआ। इससे कहीं न कहीं एकाउंटेबिलिटी स्टार्ट होगी। अन्यथा ऑफिसर वर्ग का यही सोचना है कि आपको जो भी करना है, करिये, हमको जो करना है, हम वही करेंगे। उससे इस देश के लोगों को आने वाले समय  में न्याय नहीं मिलेगा, अपने इस भाव को मैं इस बिल के माध्यम से कहने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैं अपनी पार्टी के नेता श्री आर.के.िसन्हा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस विऐाय पर बोलने का मौका दिया। देश के जो हैरान, परेशान लोग हैं, जिनकी जमीनें गईं, उनकी आवाज को यहां उठाने का मुझे मौका मिला। इसलिए मैं श्री आर.के.िसन्हा जी का धन्यवाद अदा करते हुए मोदी सरकार तथा मोदी जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि साढ़े तीन साल के कार्यकाल में जनहित के बहुत सारे मुद्दों पर यहां चर्चा करते हुए बिल में जितने भी संशोधनों की आवश्यकता है, वे करते हुए लोगों को न्याय देने का काम हम लोग कर रहे हैं।

इसलिए महोदया मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात को यहां समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय।

**श्री कौशलेद्र कुमार (नालंदा) :** अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक-2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मै आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदया, इस विधेयक के माध्यम से सरकार मूल कानून स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 की धारा 7 के खंड 1 में कुछ और विऐायों को जोड़ने का काम करेगी। मेरा मानना है कि भूमि अधिग्रहण कानून 2014 में लागू हुआ था, उसमें किसी भी सार्वजनिक कार्य के लिए सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण हो और प्रभावित व्यक्तियों को उसका उचित मुआवजा मिले, उसमें कोई आपत्ति नही है । किंतु रोजगार करने के लिए खेती और अच्छी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किसी भी मायने में कदापि उचित नहीं होगा। वैसे ही हमारे पास सिंचित और उपजाऊ भूमि की अपनी एक सीमा है। जो बंजर जमीन है, जहां खेती नहीं हो सकती है,

वैसी जमीन को उपजाऊ करने के लिए अनिवार्य कानून बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा उचित होगा और विशेऐाकर जो किसान प्रभावित होते हैं, उन्हें परेशानी नहीं होगी। अतः माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मैं एक बहुत अहम् विऐाय को सरकार के सामने लाना चाहता हूं कि जब आप अधिग्रहण का नोटिस देते हैं तो यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जो व्यक्ति सम्पति पर वर्तमान समय में कब्जा लिए हुए हैं।

किंतु वह व्यक्ति किरायेदार हो सकता है, पट्टेदार हो सकता है, उसका मालिकाना हक उस संपत्ति पर नहीं है, फिर उस व्यक्ति को नोटिस क्यों दिया जाएगा? नोटिस तो मालिकाना हक वाले व्यक्ति को मिलना चाहिए। अब यहीं से कानूनी प्रक्रिया एवं अड़चनें आरंभ होती हैं, जो वऐाॉ तक चलती रहती है। आप यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि लोग कानूनी लड़ाई में अपनी जमा पूंजी समाप्त कर लेते हैं, मात्र नोटिस की प्रक्रिया के कारण वे सब कुछ लुटा देते हैं और कंगाल भी हो जाते हैं। मेरा एक सुझाव है कि इसमें सुधार लाने की जरूरत है। अतः मेरा आग्रह भी है कि यह कानून आम लोगों को प्रभावित करेगा, इसे पूर्णतः पारदर्शी एवं न्यायोचित होना चाहिए। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद।

**माननीय अध्यक्ष :** श्री पी. करुणाकरन जी।

**श्री मोहम्मद सलीम :** अध्यक्ष महोदया, करुणाकरन जी की जगह मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूँ।

**माननीय अध्यक्ष :** ठीक है, बोलिए।

**श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) :** अध्यक्ष महोदया, मेरे प्रति आपकी करूणा के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदया, सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा, वे नए मंत्री बने हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं। विदेश के मामले से वे देश के मामले और देश की जमीन के मामले में ध्यान दे रहे हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी कानून संसद के लिए, संसद की गरिमा के लिए बहुत ही अपमानजनक होगा अगर यह कानून पारित कर के यह कहा जाए कि सन् 1952 से यह लागू होगा। It's a bad piece of legislation.

मैडम, यह जो संशोधन लाया जा रहा है, यह बहुत ही इनॉक्स है। राऐट्रीय सुरक्षा के लिए है, देश की रक्षा के लिए है, यह मंत्री जी के बयान में आया है। मैं एक क्लॉज आपको पढ़ कर बताता हूँ। मैडम, अभी थोड़ी बाद हम इसको पारित करेंगे, लेकिन क्लाज़-2 को आप देखिए, मैं पूरे देश का ध्यान आपके माध्यम से आकर्ऐित करना चाहता हूँ। यह जो संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, सन् 1952 की धारा 7 में उप-धारा-1 के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा अतः स्थापित की जाएगी और 14 मार्च, 1952 से अतःस्थापित की गई समझी जाएगी। इसका मतलब है कि मेरे पैदाइश होने से पहले और ऐसे बहुत से लोग हैं, जिनके जन्म लेने से पहले के लिए हम वह कानून बना रहे हैं। यह कौन सी परंपरा हम बना रहे हैं? यह देखने में इनॉक्स है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। भूर्मि अर्जन

का जो कानून है, ऑर्डिनेंस के बाद ऑर्डिनेंस सरकार ने लाने की कोशिश की है और वह संयुक्त समिति के पास अभी लंबित है। अभी क्या है कि अगर आप पूरे बंडल में नहीं कर पाएंगे तो पीस मील में करेंगे। एक के बाद एक राज्यों को यह कहा जा रहा है कि किसानों की जमीनों को लेने के लिए किस तरह से प्रावधान करना पड़ेगा, वह कानून बन रहा है, मैं एक के बाद एक राज्य का नाम बता सकता हूँ। यहां यह लैण्ड, एग्रीकल्चर से हट कर शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इन पीस मल में यह पीस लिया जा रहा है। मैडम, राऐट्रीय सुरक्षा के लिए, सेना के लिए, रक्षा के लिए अगर कोई कदम सरकार उठाती है तो इस पर इस सदन में कोई बहस नहीं है।

**14.42 hours**

*( Shri Sunil Kumar Jakhar and some other hon. Members then left the House.)*

लेकिन आप देखिए, कल मंत्री जी के भाऐाण में भी कहा गया कि यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब उद्देश्य में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी दो नंबर पैरा में आप देखिएगा कि लोक प्रयोजनों के लिए स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति। लोक प्रयोजन, इस देश में तो लोक प्रयोजनों के नाम पर वऐाॉ से, आप सत्तर साल की बात करते हैं तो मैं भी सत्तर साल की बात करता हूँ कि जब सरकार कोई भी विधेयक लाती है, विधि बनाती है तो सब लोक प्रयोजन के लिए होता है, पब्लिक इंट्रेस्ट के लिए होता है, लेकिन आप इसमें सिर्फ जैसे कि सुरक्षा कह रहे है, यह नहीं है कि सिर्फ सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। इस सदन को गुमराह किया जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है, यह कह कर किया जा रहा है कि हम राऐट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए यह कर रहे हैं।

नहीं, हम यह ब्लैंकेट कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि उद्देश्य हमारा जैसा कि रक्षा है। जैसा कि रक्षा लाइक डिफेंस और सिर्फ डिफेंस दोनों में फर्क है। आप तो कुछ भी सुरक्षा के नाम पर चला सकते हो और यहाँ तो लोक प्रयोजन है। पब्लिक इन्टरेस्ट के लिए तो, जब किसानों की छाती को गोली चलाकर छलनी किया जाता है तब भी आप यह कह सकते हैं कि हमने पब्लिक इन्टरेस्ट के लिए यह किया। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह हाइली ऑब्जेक्शनेबल है, हम चेयर से इस बारे में अनुरोध करेंगे। यह लोक सभा वऐाऩ 2014 से वऐाऩ 2019 के लिए बनी है। क्या हमें वऐाऩ 1952 के लिए कानून बनाने का हक है और वह किसलिए किया जा रहा है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कोर्ट में कई ऐसे मामले लम्बित हैं, कोर्ट ने कई ऐसे अधिग्रहण के नोटिस को नकार दिया है, चाहे वे पिछली सरकार के द्वारा ही क्यों न हों। आप उस सबको पोस्ट फैक्टो, उस आदेश को नकार रहे हैं, उस निर्देश को नकार रहे हैं। इतना अधिकार क्या हम सत्ता में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स को दे सकते हैं, क्योंकि उस वक्त मंत्री जी भी नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, इसके तहत जो इसका प्रयोग होगा, तो क्या हम अधिकारियों को यह अधिकार दे सकते हैं। इस देश में तो आप जानते हैं कि भूमि एक ऐसा मामला है, सम्पत्ति एक ऐसा मामला है, सिर्फ इसमें बहुत ज्यादा मुकदमे, मामले लम्बित हैं, ऐसी बात नहीं है, जो आप स्कैम की बात कर रहे हो, जो भ्रऐटाचार की बात कर रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा जरिया भूमि और सम्पत्ति है। यह हम सब जानते हैं, गाँव से लेकर पूरे देश के लोग इसे जानते हैं, इतिहास गवाह है। हम इसको इतना ब्लैंकेट कानून किसलिए कर रहे हैं और जो बिल समिति में लम्बित है, उसको हम बाईपास करके क्यों इस कानून को ला रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि आप यह कह रहे हो, जो लौटाने की बात है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हमारी पार्टी का समय भी कम है। इसी दिल्ली में, मैं कलकत्ता से आता हूँ, बंगाल से आता हूँ, जब अंग्रेज यहाँ

राजधानी ले आये तो यहाँ बहुत सी सम्पत्ति का उन्होंने अधिग्रहण किया। जहाँ राऐट्रपति भवन है, रायसीना हिल से लेकर यह पूरा हिल्स, नई दिल्ली स्टेशन आदि ये सब वक्फ प्रॉपर्टीज थीं। वऐान 1980 के दशक में सरकार ने अर्बन डेवलपमेंट से एक समिति बनाई और 123 ऐसी सम्पत्तियाँ, जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया, उसको वापस करने की बात थी और वापस कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ निर्माण भवन बना लिया, तो निर्माण करने के बाद राऐट्रपति भवन कैसे वापस करेंगे, तो उसका उचित मूल्य देना। इसमें तीन सुझाव थे कि अगर खुला है तो वापस करो, नहीं तो उसमें यह प्रावधान भी रखा है कि या आप उसको मुआवजा दो या फिर उसकी एवज में, क्योंकि उतनी डेवलप्ड लैंड नहीं थी, तो उतनी लैंड आप कहीं बाहर दीजिए। सरकार के साथ तो चलना ही पड़ेगा, यह अंग्रेजों के जमाने से चल रहा है। आपने इस कानून में उस मामले को नहीं रखा है और उसे नकार देंगे। वह अभी भी लम्बित है, बर्नी कमेटी बनी, कमेटी के ऊपर कमेटी बनी, वह केस कोर्ट में चल रहा है। हमारे एक पुराने मित्र कहते थे कि नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफार्म के ऊपर मस्जिद क्यों है? मैंने बोला कि नई दिल्ली स्टेशन में मस्जिद नहीं है, मस्जिद की जगह पर नई दिल्ली स्टेशन बना है। ऐसे ही एयरपोर्ट पर भी कभी-कभी सवाल होता है। वह वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है। वह अलग बात है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में वह लम्बित है और जिस रोज कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि इसको वापस करो, ये कांग्रेस के लोग चले गये, उस वक्त श्रीमती इंदिरा गाँधी जी प्रधानमंत्री थीं, लेकिन कोर्ट के आदेश लागू करने से पहले ही फिर स्टे ले लिया गया। एक दिन का समय दिया गया। इसी तरह से यह देश चलता है, ब्यूरोक्रेट इसी तरह से चलाते हैं और उसके बाद वह केस अभी भी कोर्ट में लम्बित है। सरकार के अटॉर्नी जनरल के बाद, एक के बाद एक सरकार के बड़े-बड़े वकील खड़े ही नहीं होते हैं। मामला ऐसे ही चलता रहता है। सम्पत्ति का मामला ऐसे ही होता है, अगर कोई हड़पना चाहे तो उसको किस तरह से हड़पा जा सकता है, यह उसका उदाहरण है। मैं इस सरकार के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा हूँ, मैं यह पुराना इतिहास बता रहा हूँ। पास्ट परफारमेंस एक इन्डिकेटर होता है, तो इसी तरह से किसी भी किसान, किसी भी नागरिक का सम्पत्ति का अधिकार उसका बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है। अगर आप उसे उससे डिप्राइव करोगे, तो यह ठीक नहीं है। आप बड़े-बड़े पूँजीपतियों के ऊपर तो हाथ डाल नहीं सकते हैं। वे रुपया मारकर ले जा रहे हैं, एनपीए हैं, वे विदेश लेकर चले जा रहे हैं, उनके ऊपर आप हाथ नहीं डाल सकते हो और जो किसान खेती कर रहा है, जो अपना घर बनाकर वहाँ बसा हुआ है। अर्बन लैंड सीलिंग के बाद अर्बन एरियाज में आजकल बहुत बड़ी सम्पत्ति होती भी नहीं है। आप उन मालिकों को उचित मुआवजा नहीं देकर के, उनकी सुनवाई नहीं करके कैसे करेंगे। लेकिन, इसकी सुनवाई किस तरह से होती है, इसे आप जानते हैं। स्टेट की बड़ी शक्ति के सामने एक छोटा-सा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो तो वे उस मामले को खींच कर सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे।

मुआवज़ा देने के बारे में मैं समझता हूं कि अगर यह सिर्फ सुरक्षा से संबंधित है तो आप इसमें मुआवज़ा बढ़ा सकते हैं। पर, जिसकी ज़मीन है, जिसकी खेती है, बेशक वह राऐट्र का प्रयोजन है और उसे आप सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, लेकिन आप मुआवज़ा बढ़ाने की बात तो कर ही रहे हैं और अगर आप वऐान 1952 के रेट पर लैंड लेंगे तो यह नहीं होगा। इसमें जो आपने दो प्रावधान किए हैं कि 'अगर अधिग्रहण का नोटिस दोबारा जारी किया जाता है', लेकिन आप दोबारा नहीं करेंगे और चूंकि आपने पुराने कानून को नकारा नहीं है तो आप उसी कानून को आगे ले जाएंगे। दूसरा प्रावधान है - 'अगर ज़मीन का अधिग्रहण राऐट्रीय सुरक्षा और रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है।' मैं कहता हूं कि इसे आप 'लोक प्रयोजन' के नाम से हाउसिंग के लिए इसे करेंगे, अगर आप मॉल बनाने के लिए करेंगे, आप तो कहेंगे कि यह सरकार ले रही है, लेकिन अभी पी.पी.पी. मॉडल का मामला है। ज़मीन राज्य सरकार लेती है, वह 'लोक प्रयोजन' के तहत ली जाती है, लेकिन बाद में पी.पी.पी. मॉडल कह कर अगर उसे प्राइवेट को दे दी जाए या पार्टनरशिप में दे दी जाए और फिर वह उन्हें हैंडओवर हो जाए तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा।

तीसरी बात है कि भूमि अर्जन से संबंधित जो समिति बनी है, मैं खुद उस समिति का सदस्य हूं। अब तो उसकी बैठकें भी नहीं होती हैं। उसकी डेट-आफ्टर-डेट लम्बित होती रहती है। उस कानून को तीन बार ऑर्डिनैंस के माध्यम से लाने की कोशिश की गयी और किसानों के हित के लिए बताई गई, लेकिन बिहार चुनावों के बाद किसानों का वह हित चला गया। उसके चेयरमैन भी यहां बैठे हुए हैं। उस समिति की बैठक भी नहीं होती है। एक तरफ तो पूरे विश्व के इन्वेस्टर्स को कहा जाता है कि हम कानून ला रहे हैं और देश में कहा जाता है कि इस कानून को लाने से किसानों का बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए अभी इसको रोक कर रखो, जब तक राज्य सभा में मेजॉरिटी नहीं आती है, तब तक हम पारित नहीं करेंगे।

**श्री भर्तृहरि महताब (कटक) :** यह किसने कहा?

**श्री मोहम्मद सलीम :** मैं कह रहा हूं।...(व्यवधान)

**माननीय अध्यक्ष :** इनको सब मालूम है।

**श्री मोहम्मद सलीम :** समझदारों के लिए इशारा काफी है। देखिए अध्यक्ष महोदया समझ रही हैं, आप तो थोड़ा समझदार बन जाइए।...(व्यवधान)

आप जानते हैं कि मैं बेबाक बोलता हूं और साफ-साफ बोलता हूं। मेरे नाम से पूरे देश में एक इंच ज़मीन नहीं है और न रहेगी। सिर्फ मरने के बाद दो गज ज़मीन की जरूरत है, उसके लिए खानदानी कब्र है। मैं वहां चला जाऊंगा। इसलिए मैं ज़मीन के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे वह लीगल हो या इल्लीगल डील हो।

मैं जहां कह रहा था, वहां से बैक करना चाहता हूं।

**माननीय अध्यक्ष :** चलिए, आप अपनी बात कम्प्लीट करिए।

**श्री मोहम्मद सलीम :** हम मुद्दे पर आ रहे हैं। रिक्वीजीशन और एक्वीजीशन का जो मामला है, इस देश में सबसे पहले जो रिक्वीजीशन हुआ, वह दूसरे विश्व युद्ध के समय हुआ। वार के टाइम में डिफेंस के लिए उसकी जरूरत थी। जो प्रॉपर्टीज़ थीं, खासकर अर्बन प्रॉपर्टीज़, चूंकि मैं कोलकाता से आता हूं, बंगाल से आता हूं, तो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को जापान का डर था, इसलिए उन्होंने उसकी रिक्वीजीशन कर ली। उसके बाद फिर उन्हें उसे वापस करना था। अभी भी ऐसी सम्पत्ति है, जिसकी रिक्वीजीशन की गयी। आज़ादी के बाद जो सरकार बनी, उसके जो चेले थे, पिट्ठू थे, वे वहां बैठे हुए हैं। सरकारी क्या, कोई काम नहीं आता है? लेकिन, वह उसी तरह से लम्बित रह गयी। प्राइम प्रॉपर्टीज़ की रिक्वीजीशन एण्ड एक्वीजीशन उसी तरह से लम्बित रह गयी। अगर आप कोलकाता शहर में जाकर चारों तरफ देखेंगे तो ऐसी रिक्वीजीशंड प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं और उन्हें वापस नहीं किया जा रहा है। चूंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ तो हमारे पास पार्टीशन की वज़ह से रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ। यह उनका मामला है, मैं यह हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं। शहरों में जब रिफ्यूजीज़ आएं तो उनकी भी पुनर्वास करने की बात थी। इसलिए उस समय उसे टेम्पररी एक्वायर किया गया। उनके पुनर्वास की जरूरत थी, लेकिन आपके उस समय के जो अधिकारी थे, तब के तमाम उसके डिसेंडेंट्स, आप जो खानदानी राज की बात करते हैं, तो यह आपका डिपार्टमेंट नहीं है, उन सबको 'कस्टोडियन ऑफ इनेमीज प्रॉपर्टीज' के नाम पर वहां रखा गया है।

मैं समझता हूं कि जैसे आप लैंड एक्वीजीशन के बारे में फेयर बात कर रहे हैं, कानून में, कम से कम नाम में, और आप उसमें ट्रंसपैरेंसी की बात कर रहे हैं तो इस रिक्वीजीशन और एक्वीजीशन के कानून में भी 'ट्रंसपैरेंसी' शब्द लाना चाहिए और पारदर्शिता दिखनी चाहिए। यह पारदर्शी है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, बल्कि पारदर्शी दिखना चाहिए।

इतना कहते हुए मैं आप से क्षमा याचना करता हूं कि मुझे थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ा।

**माननीय अध्यक्ष :** कोई बात नहीं।

**श्री मोहम्मद सलीम :** चूंकि बहुत हल्ला-गुल्ला में हमने अपनी बात शुरू की थी। लेकिन, आप देखिए, जब भी आप हमें बोलने का मौका देंगी, सदन शांत हो जाएगा। भविऐय में इस बात को आप ध्यान में रखें।

धन्यवाद।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Hon. Speaker Madam, thank you very much for giving me some time to take part in the consideration and passing of this Bill. I rise to speak on the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017 that aims to replace the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, with retrospective effect, that is, from 14 March, 1952, which is more than 65 years and four months ago, to be precise.

At the outset, I would categorically put it on record very clearly that this Bill aims to attain many goals with one stroke. I wonder 65 years and four months is too long a period to correct all the mistakes, all the damages done in between.

As per the Statement of Objects and Reasons of the Bill, the power to requisition immovable property for public purposes is provided under Section 3 of the 1952 Act and the power to acquire requisitioned property is under Section 7. The principles and method of determination of compensation for requisitioned property and payment thereof have been laid down in Sections 8 and 9 of the 1952 Act.

By proposing to amend Section 7 now the Government tries to jump over prolonged litigation traversing up to the apex court, when the interested persons are succeeding or have succeeded in getting a notice of acquisition quashed, they would-be bestowed with the unintended benefit of compensation for their property.

I am given to understand that this move has come after decades of litigation on a piece of land in Rajasthan for which the Government, if not wakes up now, might have been forced to pay more than Rs. 8000 crore. In addition, as per the Directorate General of Defence Estates, there are as many as 433

litigations due to land acquisition where the Government would have to pay a significant quantum of compensations to the owners.

Therefore, the main problem of faulty identification of a land which should not have been acquired in the first instance goes scot free. Similarly, faulty payment of compensation thereafter also goes unpunished. Therefore, by bringing in this legislation the Government is not eradicating the malady from its root but is trying to cover up the past deeds.

The 1952 Act has the provision that once the purpose for which the properties were requisitioned is over, it must be returned back to the owner in as good a condition as when the possession was taken. Under the 1952 Act when acquiring a requisitioned property, the Central Government has to issue a notification with regard to such an acquisition. Before issuing such a notice, the government has to provide the property owner an opportunity to be heard. The property owner at such hearing will have to provide reasons for why the property should not be acquired.

Now, this proposed amendment Bill provides that the Government may reissue the acquisition notice to the property owner to give them adequate opportunity for a hearing. This would be irrespective of any past court orders or judgments setting aside any past notices for acquisition. I do not know whether all the court judgements that have come in between have been properly addressed or not. I feel we must honour all the hon. Courts' orders in this regard.

The next interesting provision is about the interest payable on compensation. In the cases where a notice is reissued, the property owner or the person interested in the property will be entitled to the same annual rate of interest prevalent at any relevant time on the domestic fixed deposit offered by the State Bank of India as defined under Clause (g) of Section 2 of the State Bank of India Act 1955 on the compensation payable from the date of publication of the first notice till the final payment of the compensation. This will eventually reduce the financial burden for the Government.

As we all know, the Government is a collective group that works for the benefit of the public at large. I have no option but to support the proposed amendment Bill in its endeavour to amend the Act of 1952.

**15.00 hours**

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

Last but not least, the proposed amendments will take care of the cost variation of the land when they are sold due to non-completion of the projects by the Government.

I would thank my Party President and my Leaders for permitting me to put forth our views on this amendment Bill.

Thank you very much.

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 का संशोधन करने वाला यह विधेयक यहां पेश किया गया है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, 1952 के अधिनियम के अनुसार केद्र सरकार रक्षा विभाग से जुड़े सार्वजनिक कार्य के लिए जमीन अधिग्रहण करती है तो इसमें एक शर्त है सार्वजनिक कार्य हेतु ली गई जमीन रक्षा विभाग और केद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए उपयोग होनी चाहिए। पिछले 65 वऐाॉ में किसानों की बहुत सी जमीन अधिग्रहण की गयी। मेरे यहां पूना में दिघी, बोसरी, चरौली आदि क्षेत्रों में 1232 एकड़ जमीन रक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई थी, उसमें से 750 एकड़ जमीन टाटा टेलीकॉम कंपनी को किराये पर दी गई है। रक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई जमीन का उपयोग अगर रक्षा विभाग हेतु होता है तो ठीक है, लेकिन अगर रक्षा विभाग की जमीन दूसरे कामों के लिए दी जाती है तो जिस उद्देश्य के लिए किसानों की जमीन ली गयी थी, वह उद्देश्य पूरा नहीं होता है। आज भी देश भर में 222 प्राइवेट कंपनीज को रक्षा उत्पादन के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। रक्षा विभाग की कंपनीज में रक्षा विभाग के लिए उत्पादन होता है। आज कई कंपनीज में भारत सरकार पूर्ण रूप से उत्पादन नहीं कर रही है और आज लगभग 143 ऐसी कंपनीज उत्पादन करती हैं। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को देश के रक्षा हित के लिए जितनी जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता हो, सरकार द्वारा किसानों की उतनी ही जमीन अधिग्रहण की जानी चाहिए। जब किसानों की जमीन अधिग्रहण होती है और जिस एरिया में वह जमीन अधिग्रहण होती है, आज अगर उस इलाके में जमीन का भाव देखा जाए तो वह बढ़ता जा रहा है। इस तरह से इसमें किसानों का नुकसान होता है।

मैंने पहले भी सदन में यह बात उठाई थी, मेरे चुनाव क्षेत्र मावल में मिसाइल प्रकल्प के लिए केद्र सरकार द्वारा वऐान 2003 में 190 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गयी थी। आज तक उस जमीन का पूरा मुआवजा किसानों को नहीं मिला है। जमीन अधिग्रहण का काम स्थानीय कलेक्टर और वहां के स्थानीय अधिकारी करते हैं और केद्र सरकार को जमीन देते हैं। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण करते हैं, वे किसान आज तक कोर्ट के चक्कर काटते आ रहे हैं, कोर्ट में लड़ाई लड़ते आए हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला है। वऐान 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि रेडी रेकनर के हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। आज 65 वऐान बाद सरकार कानून में यह प्रावधान लाई है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। यह अच्छी बात है। अगर आज कानून में यह प्रावधान लाया गया है तो आगे चलकर निश्चित रूप से किसानों को इस हक के लिए कम से कम कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करता हूं कि आगे चलकर कोई किसान अगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसे कोर्ट में जाने का प्रावधान कानून में है। लेकिन सरकार में ऐसा कानून होना

चाहिए कि समझौता करके और अगर उसमें जमीन के बदले कुछ मुआवजा मिलता है तो यह कानूनी लड़ाई खत्म हो जाएगी और किसानों को अच्छी राहत सरकार द्वारा मिल सकती है।

दूसरे, जितनी जमीन का अधिग्रहण होता है, रक्षा विभाग के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है, देश के हितों के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है, लेकिन जितनी जमीन अधिग्रहीत हो जाती है, उसमें किसानों का कुछ फायदा नहीं होता। किसानों के अपने परिवार में अनेक जन रहते हैं। अगर आगे चलकर, ऐसे कोई प्रकल्प के लिए जमीन लेते हैं तो किसानों की उसमें भागीदारी होनी चाहिए।

आज कानून में प्रावधान है कि उसमें ब्याज मिलेगा। लड़ाई लड़ते हुए जितना समय जाएगा, उतने समय का उसमें किसानों को ब्याज मिलेगा। लेकिन ब्याज से किसानों के परिवारों का गुज़ारा नहीं होने वाला है। इसमें ऐसा प्रावधान होना चाहिए आगे चलकर इसमें कुछ तो किसानों की भागीदारी होनी चाहिए या उनको ज्यादा रकम मिलनी चाहिए या किसानों को सरकार द्वारा कहीं पर जमीन दी जाती है। किसान भूमिहीन नहीं होना चाहिए। यह बात मैं इसमें रखता हूं।

अंत में, मैं कहना चाहता हूं कि आज भी रक्षा विभाग के पास कई सारी ऐसी जमीनें हैं जो रक्षा विभाग की नहीं हैं। वे जमीनें आज भी कई किसानों के नाम पर हैं, लेकिन तब किसान अनपढ़ था, उसको मालूम नहीं था, रक्षा विभाग ने जब सबका सर्वे किया था, तब यह बात सामने आई थी। इसलिए जिन जिन किसानों के नाम पर वे जमीनें थीं और जिनकी जमीनों का सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया था और जिनको उन जमीनों का पैसा नहीं मिला, मेरा कहना है कि उनको आज के रेट से पैसा मिलना चाहिए नहीं तो सरकार द्वारा किसानों को जमीन वापस दी जानी चाहिए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you, Sir, for giving me this opportunity. On behalf of the Telugu Desam Party, we fully support this Bill.

Sir, where my colleague from Shiv Sena Party has ended, I will start from there. He was telling that stakeholding of the land acquisition by the State should also be with the farmers, that is, the original owners of the land. We have already done this in Andhra Pradesh. In Amravati, we have resorted to land pooling. We have pooled almost 25-30 thousand acres of land without any resistance, hitch or problem. We have acquired the land smoothly by making farmers the stakeholders. This can be emulated. My appeal to the hon. Minister is this. You can take some cue from Andhra Pradesh's experimentation of land pooling instead of forcibly acquiring through Act, legislation and enforcement. You can also requisition the land through friendly approach like we did it in Andhra Pradesh.

Sir, while introducing the Bill yesterday, the hon. Minister was telling about small farmers getting together and flocking together to form a land coterie. They will smell that this land is going to be acquired in future and therefore, they will go in for litigation. This price escalation usually takes place

after 10-15 years. Then, there will be undue benefit. The unjust enrichment will accrue to the farmers or coteries. Hon. Minister, I have a small doubt. When you said like this, you have presumed that the small farmers will form into a coterie or one land mafia fellow will make them form into a coterie. Imagine the case of a small land holding farmer - not part of the coterie - who has to sacrifice his land. Suppose his land cost was not escalated to the extent it should have been when the land was requisitioned ten years back. However, if the acquisition is taking place after ten years, then the land cost would have escalated, but the benefit is not coming to the farmers. There is a hitch in the Act to not to give any escalated value to the farmer. What have they said in the Bill? It says that the price existing at the time of requisition will be paid to the farmers including the interest payable as fixed by the State Bank of India. This is the wording of the Act. I am very afraid that this will be detrimental to the small farmers. If there is any fraudulent coterie or a vested interest coterie, fine; I agree with the hon. Minister but if there are *bona fide* farmers and small farmers who innocently held their land, then their land is taken away by the Government through this Act. So, some justice has to be done. Let us not assume everything as fraud. Let us not assume that everything is bad or negative. There can be positives also.

I would like to have one more clarification from the hon. Minister. He has said that this land acquisition is for the safety and security of the country. The safety and security of the country is ensured by the Defence as far as outside enemy is concerned. But what about the enemies within the country? There are enemies within the country also. The biggest enemy in the country is the poverty. The biggest threat to Indian fabric and secular fabric is communalism. The biggest threat to internal safety is poverty, dissents or the so called Left Wing Extremism in the tribal areas where exploitation is taking place. So, internal safety and security should also be ensured within the country. The safety and security of the people should be ensured.

Now, land is acquired for the purpose of building houses. For example, Telangana is building lakhs of houses. In that process, if they want to acquire some land, this also should be considered as internal safety and security because they are ensuring safety and security within the country. The Defence is the only agency to secure the country! I beg to differ because the people also form a major chunk of safety and security of the country. Therefore, to ensure safety and security of poor people, if the land has to be acquired for the purpose of poverty alleviation, this also should be included in this. For example construction of houses, educational institutions and health institutions for the purpose of public good is also a part and parcel of safety and security of the country.

With these words, I fully appreciate this Bill. I would like the hon. Minister to definitely address the apprehensions which I have raised on the floor of the House. On behalf of Telugu Desam Party, I fully support the Bill.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017.

Sir, on behalf of Telangana Rashtriya Samiti Party, we support the Bill. I would like to take this opportunity to draw the attention of the Government to certain issues that States face when it comes to land acquisition and a few problems that Telangana has specifically faced over the last few years.

I recently came across reports that the Government has started a process of making a central database of how much land it owns. It is an extremely welcome step and was a very long overdue. However, this tiring exercise will be useful only if these lands are put to good use. We have seen lands owned particularly by the Ministry of Defence and the Ministry of Railways remaining unused for decades together. I would request the Government to consider allowing State Governments to construct infrastructure and special welfare projects on these lands if these lands have remained idle for decades and the Ministry anticipates so in the coming years too.

The schemes of the Telangana Government like Double Bedroom Housing for providing houses to poor people would be a lot more feasible financially if unused Central Government lands were made available to us for construction.

I thank Dr. Ravindra Babu for recommending that the land should be given for Double Bedroom Scheme. He has seen that this scheme is already grounded. Very transparently, our Government has allotted double bedroom houses free of cost. We have not charged a single paisa from any person for giving double bedroom houses. But for poor people, whoever were homeless, on State Government owned land we have constructed houses, each house measuring 500 sq. ft. and provided them free of cost. If such lands are put to such use, then it would be very useful.

Very recently, the Ministry of Defence has agreed to give the Bison Polo Ground in Hyderabad for construction of the new Telengana Secretariat after prolonged negotiations. I would like to highlight the difficulties in availing, not only unused Defence lands but also the lands surrounding a Defence establishment. According to the regulations, permission needs to be taken from the local military authority if the proposed construction is within 10 meters from the outer wall of any Defence establishment and in certain cases the restriction is up to 100 meters. High rise buildings are not allowed to be constructed within these limits and restrictions on heights are laid down. Earlier, the restriction limit applied up to 500 meters and we appreciated the decision taken by the Government to relax this limit. However, what I want to raise here is the problems that one faces when the proposed construction is just beyond these limits of 10 and 100 meters. The local military authority refuses to abide by the land records of the local administrative and revenue authorities. They themselves do not conduct any land survey and thereby it becomes a hindrance when a proposed construction activity is just outside the

limits. These problems are basically more pronounced in the cantonment areas. These types of things are happening in Hyderabad Cantonment area. Earlier, the land was given to them on requisition by those people for reasons of war and all that. Now, there is a habitation of about 35000 people in that vicinity and all of a sudden they come down and put the barricades and declare that the roads are closed. It is not a good practice. The State and the people are ready to support and accommodate the requisition by the military, but they cannot come overnight with their guns totting and tanks and just say that the road is blocked and that they will not allow entry of people inside. That is not the way it should happen. A number of such problems in the cantonment areas have been brought to the notice of the Ministry of Defence. The problems have not been resolved. We wanted an alternative road. The proposal for the alternative road has already been given. So, these types of harassments should stop. I would like the Government to take a note of this issue and see to it that such practices stop.

The hon. Prime Minister has often talked about cooperative federalism. I would like to mention two things in this regard. Whenever Government makes requisition or acquires a land even for purposes of national security, it should take steps to take the State Governments into confidence. Unilateral decisions of acquiring a land without taking the State Government into confidence undermines the spirit of Centre-State relations as envisaged in our Constitution.

Secondly, I would like to request the Government to consider formulating a policy wherein land dealings between State and the Centre, should be an exchange rather than monetary purchase or lease. We had a very big problem negotiating the Bison land. When a land belonging to the Defence, which is a Government land, is given to the State Government, in return they ask for a land and in such cases, there should not be any discussion with regard to payment of money for that land. Equivalent land or double of the land that can be taken, but the Government should not consider the old registration rate of that land to the new registration rate that ought to prevail now and say that since today's registration rate of the land is more, the State Government, as per today's registration rate, has to give so much of land. That kind of a negotiation should not be there. Such a policy of land exchange instead of purchase of land would enhance and uphold the spirit of cooperative federalism in its true essence.

The hon. Minister while moving the Bill for consideration started off by saying that any sovereign State must have the power to requisition and acquire property for defence and national security purposes. While we completely agree with this, we also believe that a State should have the power to acquire property when it is meant for social welfare projects. We often see cases where acquisition is made in good faith and with fair compensation but still the acquisition is challenged and the social welfare projects get delayed due to litigation proceedings. I do want to go much into it as we have now come up with two major projects in Telangana. One is known as Kaleshwaram Project and the other is Palamuru Lift Irrigation Project. A lot of land acquisition has been done in those projects. I would not like to go into it because we have amicably taken some decisions.

Just as the Central Government incurs a loss, the State Government too incurs huge losses due to prolonged litigation and compensation which have to be paid at the increased property rates. Not only does this result into financial loss, but also stalls social welfare and developmental projects.

We request the Government which is well versed with these issues to come up with a policy to address this matter.

Lastly, I would also like to take this opportunity to particularly highlight the huge land survey undertaken by the Telangana Government in September of this year under the leadership of KCR. It is a programme that none of the previous Governments have dared to take up. We deployed more than 10,000 Government employees to undertake a comprehensive land survey over a period of 100 days and clean the ill-maintained land records. The land survey was last done during the 1930s and those records continued to be in use till date. Change of administration and officials over these years has led to increase in irregularities and confusion. Today, more than 60 per cent of the cases pending in Indian judiciary are pertaining to land titles and land records. Such a survey will put these land disputes to rest. The land surveys were to be carried out across 10,806 villages and the total land to be covered was around 1.8 crore acres. We have already completed 92 per cent of the villages covering 1.5 crore acres of land.

I urge the Government to have a look at the programme. We have initiated and requested other State Governments to adopt similar measures in order to upgrade the land records.

Sir, I invite the hon. Minister for Urban Development to please visit Hyderabad.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): I have seen those projects when the Metro Project was inaugurated.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Sir, have you seen the land survey also?

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I have seen some of the projects.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : We have done the land survey. After 1930 till today, no Government has done it. About 10, 806 villages have already been surveyed today; 92 per cent has been surveyed. Now new title is being issued. New electronic passbook is being issued. If any land transaction has to take place, you can do the transaction online itself. You can make the payment online and get the mutation done online so that there will be no problem for any person regarding mediators. Such a step has been taken very boldly and daringly by the Government of Telangana.

I would request all the other State Governments to come and see and put their records straight.

SHRI VARAPRASAD RAO VELAGAPALLI (TIRUPATI): Sir, in the proposed Amendment Bill, it has been mentioned that the Government of India can acquire land in specific cases. Instead of using vague words like these, the Government may kindly come up with the specifications and they may mention them in the amendments.

Similarly, we suggest that acquisition could be done only with regard to defence and exclusively for defence purposes only. The other word they have used is the 'national security'. That might be misused. So, what we suggest is, it should be done only for 'defence purposes' and that too only if the Government of India takes it up. Tomorrow, in case the defence production is privatised by any means, the land should not be acquired for the private people. It also has been mentioned that in some cases the land could be acquired for the housing purpose. As the land would be taken away from the poor peasants and traditional communities, I suggest that for housing purpose this kind of brutal acquisition could be avoided when it comes to the poor peasants.

With regard to the issue of compensation, differential rate of compensation could be considered as a special case. Those who are very poor, like the peasants, traditional communities, like *adivasis*, the rates could be a little more, may be four times. It is because they have to part with whatever little land once for all and they can never afford to get it back. So, I suggest that the compensation could be more generous for the marginalised people.

There is a provision for 'personal hearing'. But who would be conducting the personal hearing is not indicated specifically. So, I suggest that the personal hearing should be conducted by not less than the District Collector. Then only it could be done in a fair manner.

When the value is fixed, I suggest that the market value rather than the guideline value could be considered so that the people who are parting with their land could be satisfied at least monetarily. In most of the cases, the Rehabilitation and Resettlement is not up to the mark. These poor people are displaced and they are not provided with adequate resettlement packages. So, I suggest that these things could be incorporated in the Act itself while making the amendments to safeguard the interests of the poor people.

More importantly, if the lands are located at the periphery of the land being acquired and if the lands belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, widows, and ex-servicemen, then the land acquisition could be avoided. There is a provision also for that because this Act should be read with the original Land Acquisition Act. So, if the poor people's lands are located in the hinterland, the land acquisition of these weaker sections should be avoided totally.

The annual rate of interest has been mentioned as that of the SBI fixed deposits. But it would be too small. As of now, it is only seven to eight per cent. The poor people would be badly affected. … (*Interruptions*) My colleague who is an active Member is saying that it is less than six per cent. It

should be minimum of 18 per cent because the poor people have to wait for too long and once they part with their lands, there is no other source of livelihood for them. So, it is extremely important that a minimum of 18 per cent of interest is paid to the land owners.

For lands which are not put into use, they have mentioned a period of five years. I think they should not take that long. So, if it is not put into use within two years, it should be handed over back to the poor people.

Crop season should always be exempted in case it is half way through. For the appeal the time period given is 21 days. That is too short in case of a Government appeal. Both in case of the Government appeal and court appeal, a minimum of 90 days should be provided. A farmer has to go and talk, etc. He may not be knowing that 21 days is the total period.

It is very surprising as to why this 65-years retrospective effect is given to such an amendment. Where is the need for that? It amounts to brutal use of the Government authority. It is because for the cases that are pending for more than 65 years, the Government is going to fix their own value. It amounts to great injustice. I do not see any natural justice in this case. They can acquire the land, but the value should be fixed as per the present market value. A lot of Government land is available, but unfortunately they are not getting into the lands which are lying unused.

If a survey is done by the Government of India at the national level, those lands which are barren now could be put to use instead of taking away the fertile lands of the poor people.

Recently we visited the site of the Polavaram Project which is a national project. It is very unfortunate to hear the cries of the *Adivasis* whose lands have been taken away. But they have not been paid the compensation till date, nor have they been resettled properly. It is very unfair. They are very poor people. They cannot afford to go to court and fight against the Government. So, this kind of relief should be inbuilt to protect the interest of the poor people. The Government does not do anything deliberately to affect the interest of the poor people. Therefore, the poorest of the poor, the traditional communities, particularly the *Adivasis* and the Scheduled Castes should be protected.

Sir, whenever *Dharkast* lands are taken away, it is very unfortunate that the Government is not adequately compensating those people as if it is the Government's land. It is not true. If a person uses the land or if a person is assigned that land, I think it should be considered as his own personal *patta* land. So, if the compensation is paid, it should be paid at par with other *patta* lands.

Then, the right to property is extremely important. There is always a clash between the court and the Government. So, I would like to suggest that the right to property should be strengthened with particular reference to the poorest of the poor, particularly the *Adivasis*, the Scheduled Castes, the Ex-

Servicemen and the widows. Then only the future generations of these people would be benefited. Thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Deputy Speaker, Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to take part in the discussion on a very important Bill, that is, the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017.

Sir, the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act came into force in 1952. As the hon. Minister had stated yesterday in his opening remarks, since 1952, 11 amendments have been done and this is the 12th amendment.

First of all, I would like to seek a clarification from the hon. Minister. The Minister said yesterday that this 12th amendment is brought specifically for defence and national security purposes. I have a doubt on this point. The original Act of 1952 was to empower the Central Government to requisition any immovable property and for the public purpose of the Union Government and to acquire such property later. So, the sole purpose of the Act of 1952 was not specifically for any defence purposes or for any purpose relating to national security, but it is for any public purpose. The term 'public purpose' has a wider meaning and wider interpretation. So almost all the hon. Members here have stated that this is only for defence purposes and the purposes which are related to national security. It is entirely different and it has a wider meaning. So, I would like to get a clarification on this point from the hon. Minister.

SHRI KALYAN BANERJEE : All the Members have not said that.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Most of the Members have said that.

Sir, kindly see the implication of this Bill. Section 3 deals with requisition, Section 7 deals with acquisition and Sections 8 and 9 deal with the quantum of compensation to be determined. These are the pertinent provisions and we are going to amend Section 7 of the original Act.

What is the history of this amendment? There were many complaints stating that an opportunity for hearing was not afforded to many persons whose properties have been acquired. They have not been provided with an opportunity of hearing. So they went to the court and finally the hon. Supreme Court has given a verdict that since no reasonable opportunity of being heard has not been given, all these acquisition notices are being quashed. That means, no acquisition proceeding is pending now and it has come to a standstill. Now, the Central Government has come up with an amendment. The first notice is regarding requisition. That is according to Section 3. The second notice is coming under Section 7. It says that your property is going to be acquired, show cause as to why your property cannot be acquired

or an opportunity be given for hearing so that you can substantiate your case. Here, Section 7 is going to be amended. A beneficial verdict was given by the hon. Supreme Court. It is a pro-people judgment given by the Supreme Court. When natural justice was denied to the poor property owners, the Supreme Court held that these acquisitions were invalid, illegal and all these acquisitions proceedings have been quashed. Yes, I do agree with the financial responsibility of the Government. Then, what is the next course of action according to this Act? According to this Act, the next action can be to issue a fresh notice. It means, the market value of the property will be counted or will be estimated or will be accounted on the date of the subsequent fresh notice. Now, the Government is coming with a Bill, which is having a retrospective effect since 1952, saying: "Yes, fresh notice will be issued. As it has been directed by the hon. Supreme Court, we will issue the fresh notice. But in ascertaining and calculating the compensation, you are only entitled for not less than six per cent of interest or the interest which is being determined on the fixed deposit by the State Bank of India, according to the State Bank of India Act". That means, the beneficial verdict given to the property owners is being limited and the Government wants to get rid of the Supreme Court judgement. Hence, I oppose this Bill.

Other provisions are also there. Kindly see them. Suppose, the acquisition notice has been issued in the year 1990 and subsequently the Supreme Court found that, that acquisition notice has not complied with the principles of natural justice. Since, it has not complied with the principles of natural justice, the acquisition process has been found to be null and void and the notice is being quashed. That means, you have to initiate fresh acquisition proceedings. Instead of going for fresh proceedings, you are going to issue a fresh notice subject to condition saying: "Though a fresh notice is being issued, we are not going to commence the acquisition proceedings afresh and you are only entitled for the interest which is being provided by the State Bank of India on the fixed deposit." We all know that land is a very important factor. We know that almost all the political developments and the social developments in the country are based on land. It is the prime issue of the socio-economic, political and cultural development of our society. It plays a very vital role in bringing prosperity in the country. We know that the Left Wing extremism, Maoist movement and the naxalite movement are based on land. You can also see the Nandigram issue and the Singur issue. We know the repercussions and impact of all these acquisition proceedings. That is why, in the year 2013, the then UPA Government has enacted a landmark legislation.

SHRI KALYAN BANERJEE : At that time, you fought against us.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No, you do not know the stand of my Party. My party is having a distinct view on the Nandigram issue of West Bengal and you know it very well.

Sir, the 2013 Act is very pertinent. The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, is still before the Standing Committee. Still, it

is before the Joint Committee of Parliament. Such a landmark legislation is there. When acquisition is being taken or it is being considered, a fair and just compensation should be provided to the people who have suffered. It is also a mandatory responsibility of the society to see that the person who has suffered due to acquisition should be compensated in a proper way. So, that principle has to be adopted in the land acquisition proceedings. Thereby, I would like to say that this 2013 Act has to be brought into force and the Committee, which has been appointed for scrutiny of this Bill, may be abolished and the Bill may be made final.

Coming to the Bill, the first provision (1A) is absolutely correct. According to the judgement of the Supreme Court, this proviso has been incorporated. Coming to the two provisos – the first proviso is regarding the annual rate of interest which is being prescribed; another one is about the enhanced compensation – I would like to seek clarification from the hon. Minister because the enhanced compensation with or without interest awarded by the court or other authority, before the date of commencement of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Act, 2017, shall be subject to the re-issuance of a notice under this sub-section and shall be applicable only to the cases of land being acquired for national security and defence purposes. Even if the enhanced compensation is awarded by the land acquisition authority or any other court or whatever it may be, you are only entitled for enhanced compensation if the property is being acquired for national security purposes or for defence purposes. Then only you are entitled for enhanced compensation. Suppose the court has made a verdict that you are entitled for this much quantum of compensation, even if the court or the authority concerned makes an order of enhanced compensation for a property other than the property relating to national security or defence purposes, then one is not entitled for enhanced compensation. That will be subject to issuance of subsequent notice which means it will be having a retrospective effect to 1952. That is totally unfair. That is why I would like to say a benefit which has been given after the legal fight in the Supreme Court, a beneficial right which has been accrued to the poor people of this country, the Government of India, by means of this amendment, is trying to restrict and limit the right of the poor people who have relinquished their land for public purposes, for defence purposes. Hence I oppose this Bill and also I would like to seek clarifications from the hon. Minister on these aspects. Thank you very much, Sir.

SHRI M. UDHAYA KUMAR (DINDIGUL): Hon. Deputy Speaker, Sir, Vanakkam. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017 seeks to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952.

The 1952 Act empowers the Central Government to requisition any immovable property and also to acquire them under certain specified conditions. Now, this Bill provides that the Government may

re-issue the acquisition notice to the property owner, or a person interested in the property, to give them adequate opportunity for a hearing.

This would be irrespective of any past court orders or judgements setting aside any past notices for acquisition. However, the re-issue of notice will not apply to cases where compensation has already been awarded and accepted by the claimants. It has been introduced amid instances of persons interested in a property challenging the acquisition move citing that they were not given any opportunity for personal hearing.

According to the Government, there could be situations that result in prolonged litigations and if the apex court quashes the notice of acquisition, there might be astronomical hike in compensation amount on account of market value appreciation.

Sir, through a recent ruling, the Madras High Court has ordered return of 7.83 acres of land worth several crores of rupees now, at Maraimalai Nagar near Chennai to children of a freedom fighter. The court also ruled that the movable and immovable properties held by freedom fighters and defence personnel should never be acquired by Government for any purpose. That has been elaborately cited in the judgement recently rendered by the hon. Madras High Court.

There are instances of families or family members who have not received adequate compensation even after several years of their lands being taken possession by the Government for their projects. In certain cases, the lands taken from the people by the Government have not been utilized to the full extent and the lands are still kept in Government possession as vacant lands.

There are also instances where the acquired properties had been utilized for other commercial purposes, much against the purpose for which the land had been originally acquired.

There are instances when the courts have directed the Governmental authorities to re-convey the lands to the original owners or their blood relatives when they found that the acquired land has not been utilized for the purpose for which it was acquired.

Against this backdrop, the Bill seeks to amend a Section of the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952 to enable the Central Government to re-issue the notice of acquisition to the owner or such other person interested in the property, for the purpose of giving “opportunity of being heard”.

In cases where a notice has been reissued, the property owner will be entitled to an interest on the compensation payable to them. The interest will be calculated for the period from when the first notice was issued till the date of the final payment of compensation. This interest will be same as the annual

rate of interest, prevalent at any relevant time, on the domestic fixed deposit offered by the State Bank of India.

With regards to the applicability of enhanced compensation, the Bill provides that such enhanced compensation will be awarded only if the acquisition notice has been re-issued, and the land is being acquired for the purpose of national security and defence.

The Governments in various States also have their own Acts with regard to the requisitioning and acquisition of immovable property and there are instances where the Centre has taken over the lands belonging to States, municipal corporations and local bodies/institutions for the purpose of defence and national security. Although there were hardly any legal entanglements between the Centre and the States with regard to the acquisition and requisition of Government lands, I wish that the hon. Minister would clarify whether the State Governments, municipal corporations and local bodies also fall under the ambit of this Bill.

Thank you.

**श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ... (व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: This is not the Bill. You have to speak on the next Bill. You please sit down.

Now, Dr. Shrikant Eknath Shinde. You take two minutes.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, I will take five minutes.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to take two minutes only.

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Sir, thank you for giving me the opportunity to speak on the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 2017.

आज इस बिल में जो अमेंडमेंट किए हैं, अमेंडमेंट ऑफ सैक्शन 7, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि आज बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी नेवाई एक गाँव है, उस गाँव में 1600 एकड़ जमीन का

नेवी ने अधिग्रहण किया है, लेकिन आज तक वहाँ के लोगों को काम्पन्सेशन नहीं मिला है। इस बिल के माध्यम से, इस प्रोविजन के माध्यम से आज लोगों के पास सुनवाई का मौका है और वह मौका इस बिल के माध्यम से लोगों को जरूर मिलेगा, मैं ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र के नेवाई में आये दिन आन्दोलन हो रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तब की ब्रिटिश सरकार ने यहाँ के किसानों की करीब 1600 एकड़ जमीन ली थी। महायुद्ध के दौरान डिफेंस कोआर्डिनेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के जरिए डिफेंस ऑफ इंडिया रुल्स के नियम 75 ए (एक) के अनुसार आदेश पारित कर रिक्विजिशन के तहत जमीन ली थी। उस नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि एक बार युद्ध खत्म होने के बाद छह महीने के अंदर वह जमीन किसानों को वापस दी जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज सात दशकों के बाद भी उन किसानों को अपनी जमीन नहीं मिली है। वह जमीन उन्हें वापस नहीं दी गई है। गए जून महीने में वहाँ पर एक बहुत बड़ा जन-आन्दोलन खड़ा हुआ और उसके कारण काफी सारे किसान दो-तीन महीने के लिए जेल में चले गए। आज किसानों को अपने हक के लिए, अपनी जमीनों के लिए अपनी ही सरकार से लड़ना पड़ रहा है। यह हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पहले यह जमीन वायु सेना के कब्जे में थी, अब कागजातों पर किसानों को बिना बताए नेवी का नाम डाल दिया गया है। बीच में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी अपना दावा ठोंका था। किसानों को बिना बताए पहले आर्मी, फिर नेवी, आर्मी से यह जमीन नेवी के पास कैसे गई और रिक्विजिशन से यह एक्विजिशन कैसे हुआ, इस पेपर की किसानों की माँग है, उसकी किसान हमेशा माँग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। हमने तब के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर जी और स्टेट डिफेंस मिनिस्टर भामरे जी से इन किसानों की दो-चार बार मीटिंग भी कराई है, लेकिन अब तक यह मामला सुलझा नहीं है। मेरी इस सरकार से दरख्वास्त है, मंत्री जी से मेरी दरख्वास्त है कि यह जो बिल है, इस बिल के माध्यम से, जो किसान प्रभावित हैं, उन किसानों को अपनी बात रखने के लिए मौका मिलेगा। आज नेवाई में बीस गाँव ऐसे हैं, यह 1600 एकड़ का जो परिसर है, उस 1600 एकड़ में बीस गाँव बसे हैं। आप मुझे बताइए कि इन बीस गाँवों को आप हटाएंगे कैसे, इतने लोगों को हटाना मुश्किल है, लोग सालों से वहाँ पर खेती कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि केद्र सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले और जो काम्पन्सेशन की बात है, केद्र सरकार कह रही है कि हम काम्पन्सेशन दे चुके हैं, लेकिन जो पेपर्स हैं, वे पेपर्स अभी तक किसानों को प्रोवाइड नहीं किए हैं। वे पेपर्स किसानों को दिए जाने चाहिए। किसानों के साथ केद्र सरकार की एक मीटिंग होनी चाहिए और आज के रेट से उनको काम्पन्सेशन मिलना चाहिए। अगर उन्हें काम्पन्सेशन नहीं दे सकते हैं तो जिन लोगों की जो जमीन अधिग्रहीत की है, वह उन्हें वापस दी जाए। उसमें भी हम एक बीच का मार्ग निकाल सकते हैं कि अगर हम इसके बीच में स्टेट गवर्नमेंट को लाएं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो जमीन है, केद्र सरकार उनको कह सकती है कि एक बीच का मार्ग देकर जो-जो प्रभावित किसान हैं, उन किसानों को जमीन के बदले जमीन हम दे सकते हैं। इससे अच्छा मुआवजा किसानों के लिए कुछ नहीं होगा। मैं एक बार फिर से सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आज इतने सालों के बाद एक प्रावधान, एक अमेंडमेंट इस बिल में लाया गया है। इससे किसानों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। मैं एक बार फिर से सरकार को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Mr. Deputy-Speaker, Sir, 15 hon. Members have addressed different

provisions of the Bill and some very valuable suggestions have been made. Since I am addressing this august gathering almost as a first timer, I had the privilege of introducing this Bill yesterday, I may not, by virtue of my own newness to the House and inexperience, be able to address each one of the points made, but I will try and address the more substantive points which have a bearing on the Bill.

One of the hon. Members said that this is an amendment – and I should add that this Act has already been amended on 11 earlier occasions and this is the 12th amendment – which is being brought for a very limited and specific purpose.

Then, I had mentioned, and one of the hon. Members also reminded me, that any sovereign State must have the power to requisition and then acquire land for the purposes of defence and national security. So, I want to repeat that. It must have that power. Otherwise, the sovereign State cannot perform its functions; it cannot provide security, the defence, which is a Central subject. But, at the same time, the State has a corresponding obligation and that obligation relates to the payment of compensation.

As I had mentioned earlier, when I introduced the Bill though somewhat hurriedly, that the State has no intention of not honoring that obligation. The State wants to pay compensation and it wants to pay fair and just compensation. But let me explain as to why this amendment has become necessary.

Section 3 provides for land to be requisitioned by the Central Government for national security and defence purposes. So, let there be no ambiguity. This is not a power of a State Government, or any other body cannot exercise it. But, it is the Central Government that does it.

Then, there is Section 7, which provides that the land or assets so requisitioned can then be acquired within a period of 17 years. The issue here is, the compensation which you pay is paid at the point of acquisition. That is the limited point.

Why is that point becoming relevant? It is becoming relevant because some parties, when they have their assets acquired, may either keep quiet about it for some time or they choose through collusion to go to the Court. As the hon. Member, Shri Ramesh Bidhuri suggested earlier, the person whose land is being acquired knows fully well that the land has been acquired by the State agency and it is a completely safe acquisition.

So, at what point do you pay compensation? According to the Act, you should pay compensation when the notice for acquisition is issued. But some people will go to the Court and challenge that notice for acquisition on the condition that they have not been provided a hearing. So, we have to remove that lacuna. But, let us hypothetically say that there is a five year gap between the first notice of acquisition and the second notice of acquisition. Will you pay compensation on the date of first notice of acquisition or on the date of second notice of acquisition when in the interim period because of

Government intervention and because of the fact that the Government has brought substantive improvements to the land, the land value has shot up?

Then, one hon. Member said कि कम्पेनसेशन नहीं दिया जा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट बहुत कम है। No, it is not a compensation or interest situation at all. In the interim period till you get your compensation, you will be paid interest according to the Fixed Deposit rate of the State Bank of India, which is between 6 and 9 per cent.

Let us say, in other words, taking a hypothetical case, you had your requisition done in 2000. But the notice of acquisition was challenged in a Court. The Court took up the challenge and it is coming up, let us say, 10 years later. There is one of two possibilities when you challenge it. The challenge is there because the party has not been provided an opportunity to be heard. You provide an opportunity to be heard and then the Court dismisses it. What does the Court do? The Court then will settle it saying that this is done. You pay compensation at the market rate prevailing in 2010 or in 2000. There is a substantial difference in the rate in those 10 years. Another hon. Member brought up the issue of another Act which is the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. That Act stays. You follow its provisions. This amendment is solely for the point of determining the date for the compensation to be computed.

**16.00 hours**

Will it be done on the date of the second or final notice for acquisition under Section 7? In case where the court dismisses the take over, the State has one or two responsibilities. If the amount of compensation being demanded is too high, the State should either pay it or the State should say that it foregoes the asset. In either case, there is no question of a poor farmer being deprived.

Let me also try and address some of the other concerns. There was a concern raised about the enemy within. I completely agree that when you are dealing with issues of national security, defence, that is the enemy slightly more visible across the border. Or, when our western neighbour unleashes terror as an instrument of policy, that enemy is not visible. But you have an enemy within - poverty. I have absolutely no doubt that terrorism actually thrives where there is poverty and you have to address that. That is something which the Prime Minister and this Government is trying to do through other schemes, like providing electricity connections free to the villagers, providing housing under Pradhan Mantri Awas Yojana, providing affordable housing for the economically weaker sections and providing housing for the lower income groups. That is an entirely separate category.

Mr. Deputy Speaker, Sir, in the kind of scenario we are dealing now, these are not poor farmers whose land has been suddenly acquired. The farmers may have at some stage been short-changed. I have no doubt about that. Somebody who has resources and who can use the system of the courts, acquires small parcels of land from farmers and pays them compensation which, I have no doubt, would

not have been adequate or appropriate. That person, then, gets into a situation with the State because of an acquisition under the Act of 1952. We are now trying to check that unintended benefit and profiteering which would accrue as a result of misuse of those provisions.

Sir, in other words, I welcome the wide-spread support that this Bill has received. I also believe that the doubts which had been expressed essentially stem from, perhaps, an inadequate appreciation of the provisions of this Bill. An hon. Member asked how it is only for national security and defence. It is clearly given in the proviso that it is only for national security and defence.

Also, a very important clarification, which might address some of the doubts, is that the Government has no intention to open up cases where compensation has already been provided and where the recipient has already received the compensation. So, there is no intention to open up those cases.

As I said, there are many more issues which have been raised. Some of them may not have a direct bearing or relevance on the Bill, but I did tell my colleague here that I will confine myself because you wanted to maybe take up the next Bill.

Also, I have another Bill coming and I think, one of the hon. Members has already foreshadowed that discussion.

With these limited words, I recommend and commend the Bill for adoption. Thank you very much.

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

> "That the Bill further to amend the Requisitioning and Acquisition of Immovable Property Act, 1952, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

**CLAUSE 2 Amendment of Section 7**

HON. DEPUTY SPEAKER: There are amendment Nos. 1 and 2 to Clause 2 to be moved by Shri N.K. Premachandran. Are you moving your amendments?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving the amendments, but I want to seek one clarification.

Hon. Minister is reiterating the fact that it is only for national security and defence purpose. Only second proviso is regarding that. The other section is for all the public purposes. Please correct me.

SHRI HARDEEP SINGH PURI: I want to state for record that the 1952 Act deals with acquisition of land for public purposes.

I am not getting involved with it. This Amendment is specifically to deal with the Government of India's acquisition under Section 7 for national security and defence purposes only.

HON. DEPUTY SPEAKER: Okay. The question is:

"That clause 2 stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 2 was added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.*

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the hon. Minister may move that the Bill be passed.

SHRI HARDEEP SINGH PURI : I beg to move:

"That the Bill be passed."

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*